Title: Requested to prefer the people's representatives at the time of selection of committee members of Government Boards and Corporations.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सार्वजनिक उपक्रमों के तहत विभिन्न बोर्डों और निगमों में आए दिन नौकरशाहों को अध्यक्ष मनोनीत करने की परिपाटी का सिलसिला शुरु हो गया है। इन बोर्डों और निगमों में दोनो सदनों के सदस्यों को मनोनीत करके भेजा जाता है। जो माननीय सदस्य इसमें नॉमिनेट होकर आते हैं, उनकी अपनी-अपनी कार्य कुशलता है, अनुभव है और उनका अपने क्षेत्र में काफी महत्व है लेकिन उन नौकरशाहों की अध्यक्षता में गठित समितियों में जन प्रतिनिधियों को सदस्य बनाना जन प्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा है, अपमान है। सरकार फिलहाल कई बोर्डों और निगमों का पुनर्गठन करने जा रही है जैसे शिपिंग कार्पोरेशन। मेरा अनुरोध है कि ऐसे बोर्डों और निगमों के गठन के समय जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने पर सरकार विचार करे।